Observation made in the International Confernecc on AIDS Held at Vancouver, Canada

2575. SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether International Conference on AIDS, held at Vancouver Canada earlier this year, observed that while the spread of AIDS is by and large confined to developing countries, India has the dubious distinction of having the largest number of infected cases; and

'(b) if so, the number of full blown AIDS and HIV infacted cases in country as compared to that in other developing and developed countries, indicating also the fatal cases, since the virus was indentified?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) The observations at the Vancouver Conference inter-alia related to lndia having more infected people than any other country but this was based on statistical estimates and not on a survey of actual cases.

(b) In India, as reported up to 30th Nov.. 19%, there are 4877 HIV positives 308(1 AIDS cases and number of deaths due to AIDS arc 723. A comparative chart indicating AIDS cases in some of the developing and developed countries is given below:

1. Thailand	44471
2. Kenya	69005
3. Brazil	82852
4. France	43451
5. Spain	41589

राष्ट्रीयकृत बैंकों / वित्तीय संस्थाओं में जमा की गई धनराशि

2576. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ख) उसका राज्य-वार, बैंक-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों के बोलने की अनुमति दिये जाने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं में जमा धनराशि में कमी आई है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई सूचना के अनुसार मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियां बैंक-वार विवरण-I में और राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र-वार विवरण-II में दी गई है (नीचे देखिए)। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1994 में गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आगमन से अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियों में कोई गिरावट नहीं आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि केवल चुनी हुई अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सावधि जमाराशियां और जमा प्रमाणपत्र (सी डी) स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। वित्तीय संस्थाएं सीमित आधार पर निधियों के स्रोत के रूप में जमाराशियों पर निर्भर करती हैं। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा जुटाई जाने वाली जमाराशियों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं को जिन शर्तों पर जमाराशियां जुटाने की अनुमति दी जाती है वे उन शर्तों से भिन्न है जिन पर बैंक जमाराशियां जुटाते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थाओं के निवेशकों का घटक बैंकों से भिन्न होता है जिन्हें लक्ष्य बनाकर जमा राशियां जुटाई जाती हैं। इसलिए, गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के खुलने से वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाई जाने वाली जमाराशियां प्रभावित नहीं हो सकती।